न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता के समक्ष

गुरबचन सिंह और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

अमरीक सिंह और अन्य-प्रतिवादी

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1810/1973.

4 अक्टूबर 1982.

सिविल प्रक्रिया संहिता (5/1908) - आदेश XXVI नियम 9 और 10 विवादित भूमि के सीमांकन के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त - आयुक्त की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई और मुकदमे का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया गया - दूसरे आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया - न्यायालय ने यह राय दी किसी अन्य आयुक्त की नियुक्ति से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा–दूसरे आयुक्त की नियुक्ति–चाहे यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर हो।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVI नियम 9 में स्थानीय जांच के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। आदेश XXVI का नियम 10 आगे आयुक्त की प्रक्रिया प्रदान करता है। ट्रायल कोर्ट को आगे की जांच का निर्देश देने का विवेकाधिकार दिया गया है क्योंकि वह किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में उचित समझ सकता है। यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि नियम 10 के खंड (3) के तहत, ट्रायल कोर्ट या निचली अपीलीय अदालत किसी अन्य आयोग को नियुक्त करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के तहत है, जब वह पहले से नियुक्त आयोग की कार्यवाही से असंतुष्ट है। इस प्रकार, संहिता के

आदेश XXVI के नियम 10 के उप-खंड (3) को पढ़ने या प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि किसी अन्य आयुक्त को नियुक्त करना न्यायालय का विवेक है और ऐसा करना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है, खासकर जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(पैरा 9, 10 एवं 13)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, , करनाल के न्यायालय के दिनांक 7 सितंबर, 1973 के निर्णय के जिसने उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, करनाल (दिनांक 12 मई 1970) के निर्णय की पुष्टि की, जिसके तहत वादी का मुकदमा प्रतिवादी की लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।

दावे: खसरा नंबर 11176/145 वाले प्लॉट नंबर 13 पर कब्जे के लिए मुकदमा, जिसकी माप 1 एकड़ 7 मरला है, जो करनाल में स्थित है, जैसा कि वादपत्र के साथ संलग्न योजना में लाल रंग में दिखाया गया है। अपील में दावा: या निचली अदालतों के आदेश को उलटना।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील अरुण जैन के साथ वकील एन.सी. जैन और वकील वी.के. जैन।

वी.के. बाली, प्रतिवादियों के वकील।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) यह वादी की दूसरी अपील है जिसका भूमि पर कब्जे का मुकदमा नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(2) वादी-अपीलकर्ताओं ने खसरा नंबर 1176/1445 वाले प्लॉट नंबर 13 में से जमीन के एक हिस्से पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादी के पूर्ववर्ती हितधारक मुकंद सिंह ने यह प्लॉट खरीदा था। 1 एकड़ 7 मरला नापने के लिए रु. पुनर्वास विभाग से मार्च, 1956 को 36,650 रुपये प्राप्त हुए और उन्हें 12 जून, 1957 को कृषि भूमि का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा दे दिया गया। उक्त मुकंद सिंह ने लाभा माई, वादी नंबर 5 सहित कुछ दावेदारों को भी अपने साथ जोड़ा था, जिनके दावों को बिक्री भूमि के टुकड़े के भुगतान के लिए समायोजित किया गया था। निकटवर्ती भूखंड खसरा नंबर 1446, कोठी नंबर ए-75 को पुनर्वास विभाग ने गोपाल सिंह और अन्य को बेच दिया था, जिन्होंने बाद में इसे प्रतिवादियों को बेच दिया। वादी के अनुसार, प्रतिवादी ने वाद पत्र के साथ संलग्न योजना में ए बी सी डी ई के रूप में वर्णित भूमि के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे प्लॉट संख्या 13 का एक हिस्सा बताया गया है।

(3) प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दाखिल किया जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मुकदमे की संपत्ति प्लॉट नंबर 13 का हिस्सा है। उन्होंने दलील दी कि मुकंद सिंह ने केवल 7 कनाल और 14 मरला जमीन बेची, न कि 1 एकड़ और 7 मरला जमीन। वादपत्र में आरोप लगाया गया है।

(4) पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दा तय किया: -

“ (1) क्या विवाद की भूमि वादी की है और प्रतिवादियों ने उस पर अतिक्रमण किया है।

(2) राहत।"

(5) ट्रायल कोर्ट में, क्षेत्र संख्या 11176/1445 के सीमांकन के लिए एक स्थानीय आयोग जारी किया गया था जिसे श्री ओम प्रकाश वैद, तहसीलदार, करनाल द्वारा निष्पादित किया गया था। उनकी रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा आपत्तियां दाखिल की गईं क्योंकि रिपोर्ट वादी पक्ष के पक्ष में थी। इन आपत्तियों के कारण, ट्रायल कोर्ट ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट की वैधता तय करने के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

“ (1) क्या आपत्ति याचिका में उल्लिखित आपत्तियों पर स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट रद्द की जा सकती है?

(2) राहत।"

(6) ट्रायल कोर्ट ने अंततः प्रतिवादियों की ओर से दायर आपत्ति याचिका को स्वीकार कर लिया और स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। गुण-दोष के आधार पर, यह निष्कर्ष निकला कि वादी रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह साबित करने में विफल रहे हैं कि विवादित भूमि खसरा नंबर 11176/1445 का हिस्सा है, जैसा कि वादी ने आरोप लगाया है। "इस निष्कर्ष के

परिणामस्वरूप, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। अपील में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष की पुष्टि की, हालांकि कुछ बिंदुओं पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलट दिया गया था, लेकिन यह इस अपील के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अंततः, वादी के मुकदमे को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया।

(7) निचली अपीलीय अदालत से एक अन्य आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन निचली अपीलीय अदालत ने उक्त अनुरोध को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि "मामले को वापस भेजने या स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा"। इससे असंतुष्ट होकर वादीगण इस न्यायालय में द्वितीय अपील में आये हैं।

(8) मुख्यतः, विवादित स्थल खसरा संख्या 11176/1445 का हिस्सा है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। चूंकि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने समवर्ती रूप से माना है कि वादी विवादित स्थल को उक्त खसरा संख्या का हिस्सा साबित करने में विफल रहे हैं, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यह एक उपयुक्त मामला था जहां सीमाओं का सीमांकन करने के लिए एक अन्य स्थानीय आयुक्त को नियुक्त किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील के अनुसार, ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट वादी पक्ष के पक्ष में थी और, इसलिए, यह परिस्थितियों के अनुकूल था कि, यदि उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था, तो ट्रायल कोर्ट को एक और आयोग नियुक्त करना चाहिए था या, किसी भी मामले में, निचली अपीलीय अदालत को मामले को वापस भेजना चाहिए था या एक अन्य आयोग नियुक्त करना चाहिए था। ऐसा करने में विफल रहने पर, जो निष्कर्ष निकाला गया वह गलत है। अपने तर्क के समर्थन में,

उन्होंने पोहलू राम बनाम ग्राम पंचायत धरमगढ़ उर्फ बदोवाल, के. रामलिंगम बनाम एम. वी. रामनाथन और देबेंद्रनाथ नंदी बनाम नाथा भुइयां का हवाला दिया ।

(9) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरी सुविचारित राय है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 9 में स्थानीय जांच के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। आदेश XXVI का नियम 10 आगे आयुक्त की प्रक्रिया प्रदान करता है।
नियम 10 के खंड (3) में प्रावधान है कि:

"क्या न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से असंतुष्ट है, वह ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे।"

(10) इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट को आगे की जांच का निर्देश देने का विवेक दिया गया है क्योंकि वह किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में उचित समझ सकता है। यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि इस प्रावधान के तहत, ट्रायल कोर्ट या निचली अपीलीय अदालत किसी अन्य आयोग को नियुक्त करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के तहत है, जब वह पहले से नियुक्त आयोग की कार्यवाही से असंतुष्ट है।

(11) पोहलू राम के मामले में (सुप्रा) पक्षों के बीच विवाद का मुद्दा यह था कि क्या विवाद में निर्माण करके वादी ने गांव की सर्कुलर रोड पर अतिक्रमण किया था। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार इस मामले का निर्णय केवल मौके पर माप करके ही किया जा सकता था जिसके लिए

एक आयुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक था। माना जाता है कि उस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी भी स्तर पर कोई आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया था। के. रामलिंगम के मामले (सुप्रा) में, यह माना गया था कि जहां एक विशेष मामला पहले से ही जांच का विषय रहा है और इस संबंध में एक आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसी उद्देश्य के लिए एक और आयोग आमतौर पर तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित पक्षों द्वारा बनाए गए वैध आधारों पर यह नहीं पाया जाता कि पिछली रिपोर्ट अविश्वसनीय है और इसलिए, इसे अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, किसी भी तरह से, ये निर्णय अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क का समर्थन नहीं करते हैं। देबेंद्रनाथ नंदी के मामले (सुप्रा) में, विद्वान न्यायाधीश, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसे रिमांड पर ट्रायल कोर्ट में वापस जाना चाहिए ताकि अदालत एक उपयुक्त आयुक्त की नियुक्ति कर सके। उस सटीक मामले की जांच करना जो पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थानीय जांच के लिए आयुक्त को भेजा गया था।

(12) विभूति भूषण बैंक और अन्य बनाम साधन चंद्र शीट और अन्य में, उत्तरदाताओं की ओर से उद्धृत किया गया, यह माना गया है कि आयुक्त की रिपोर्ट की स्वीकृति या अस्वीकृति पूरी तरह से न्यायालय की क्षमता के भीतर है। इस मामले में उसके पास पूर्ण विवेकाधिकार है लेकिन उक्त विवेक का प्रयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। यदि न्यायालय विवेक के उचित प्रयोग के बाद आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज कर देता है और मामले के निपटान के लिए रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों को पर्याप्त मानता है, तो अदालत के लिए दूसरी जांच का आदेश देना अनिवार्य या अनिवार्य नहीं है।

(13) इस प्रकार, बार में उद्धृत उक्त अधिकारियों के अवलोकन से और आदेश XXVI, नियम 10 उप खंड (3), सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि किसी अन्य आयुक्त को नियुक्त करना न्यायालय का विवेक है और ऐसा करना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है, खासकर जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वर्तमान मामले में, निचली अपीलीय अदालत ने अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए इस अनुरोध पर विचार किया, लेकिन पाया कि वास्तव में, मामले को वापस भेजने या स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(14) मामले की योग्यता के संबंध में, निचली अपीलीय अदालत ने मामले पर विस्तार से चर्चा की है और एक ठोस निष्कर्ष दिया है, जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर आधारित है। यह अभिनिर्णीत किया गया है कि यह साबित नहीं हुआ है कि विवादित स्थल उस क्षेत्र का हिस्सा था जिसे वादी के पिता मुकंद सिंह को वादी में उल्लिखित खसरा संख्या के कुल क्षेत्रफल में से बेचा गया था। आगे यह देखा गया है कि ऐसा हो सकता है कि वादी के पिता के पक्ष में बेचे गए क्षेत्र में विवादित खसरा संख्या के अलावा शेष खसरा संख्या का क्षेत्र शामिल हो।

(15) इन परिस्थितियों में, मुझे निचली अपीलीय अदालत के फैसले में ऐसी कोई कमजोरी या अवैधता नहीं दिखती, जिससे दूसरी अपील में हस्तक्षेप किया जा सके। नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh